DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPER NEW DELHI | SATURDAY, 4 MARCH, 2023 ED----------

Capital set to get its 4th prison to house high-risk prisoners

NEW DELHI: Delhi will soon get its fourth jail in Narela to house high-risk prisoners, with the Centre allocating Rs 120 crore for the prison complex modelled on the Cellular Jail in the Andaman and Nicobar Islands, officials said on Friday.

"The idea behind the project is to ensure that those prisoners, who are in jail because of offences committed against the state, remain in isolation. Although there are isolation facilities in the other three jails in Tihar, Rohini and Mandoli, the new prison complex will solely house such prisoners who are a threat to society," an official privy to the development said.

The Ministry of Home Affairs will be allocating Rs 120 crore for the construction of this prison complex, he said.

He said funds will also be sought from the Delhi government in the upcoming budget for the project.

"The Delhi Development Authority (DDA) has allotted land for the jail in Narela. According to the rough plan, the prison will have 250 cells and has been modelled on the Cellular Jail in the Andaman and Nicobar Islands," the official noted.

According to officials, the prison will also have reformative facilities like Yoga, a factory where inmates can engage themselves in making certain things, among others.

"The purpose of a jail is to serve as a reformation centre. This jail, even though it will house the likes of terrorists and gangsters, will have such facilities like yoga. We will soon chalk out a plan to have more of these engagements," the official said.

He, however, said the project is at a nascent stage and after the funds arrive from the Centre, the work on the project will be expedited.

Asked if the new prison will house high-profile prisoners from other neighbouring states as well, the official said, "The priority is to house prisoners lodged in Delhi jails, but if we receive a request or some directions, it will have to be followed." AGENCIES

DDA & WWF-INDIA HAVE JOINED HANDS FOR THIS FESTIVAL

City to host bird fest at Sanjay Van on Sunday

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Nature walks to spot resident and migratory birds, interaction multimedia exhibits and workshops have been planned as part of a bird festival that will be hosted in the sylvan Sanjay Van on Sunday.

The Delhi Development Authority (DDA) and WWF-India have joined hands for this festival, the DDA announced on Friday, coinciding with the World Wildlife Day.

"Delhi is the second most bird-rich capital city in the world. Home to a staggering diversity of resident bird species, the bustling metropolis also welcomes winter and summer visitors and passage migrants who stop by on their incredible journeys," according to an official statement.

Sanjay Van, a reserve forest in the heart of Delhi, supports over 200 species of birds, it said.

WWF-India has curated the 'Sanjay Van Bird Festival' as a series of events for the people of Delhi to experience and celebrate birds in the city. This is an extended commemoration of the World Wildlife Day (March 3), organisers said.

"We have a lot to learn from birds — patience, resilience, resourcefulness, teamwork, perseverance, adaptability, vigilance and creativity. The Sanjay Van Bird Festival is an endeavour to work with nature, rather than against it. We have successfully held a Moth Festival, Dragonfly Festival as well as numerous nature trails on flora and fauna with experts in the Sanjay Van," Peush Kumar, Deputy Director (Landscapes), DDA, was quoted as saying in the statement.

Launch of a first-of-its-kind publication showcasing select resident and migratory species of birds in Sanjay Van will also be a part of the event.

Karan Bhalla, COO, WWF-India said, "With over 200 bird species at Sanjay Van, witnessing the festival will be an enriching journey involving the city's residents of all ages, in knowing and protecting the wonderful natural habitats in our midst."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। शनिवार • 4 मार्च • 2023 | राष्ट्रीय सहारा | DATED

डीडीए का संजय वन बर्ड फेस्टिवल कल से

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

- संजय वन को 'लर्निंग विद नेचर' हब बनाने की योजना
- डीडीए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया का साझा आयोजन

BIRD FESTIVAL

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 'संजय वन बर्ड फेस्टिवल' के आयोजन की तैयारी पूरी हो गई है। 5 मार्च से शुरू होने वाले इस आयोजन की जिम्मेदारी डीडीए ने डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया को सौंपी है। इस वर्ड फेस्टिवल की खासबात यह है कि आने वाले लोगों को पक्षियों की विविधता से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए पारस्परिक संवाद से संबंधित गतिविधियों से जोड़ने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। बर्ड फेस्टिवल के इच्छुक एवं पक्षी प्रेमी 'bit.ly/SanjayVanBirdFestival' पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्राधिकरण का मानना है कि इस आयोजन से दुनिया से आने वाले वन्यजीवों को बढ़ावा मिलेगा।

डीडीए का दावा है कि दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पक्षियों वाली राजधानी है। यहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आने वाले पक्षी आते हुए और लौटते हुए राजधानी में बसेरा जरूर करते हैं। प्राधिकरण का यह संजय वन रिजर्व फॉरेस्ट 200 से अधिक पक्षियों का आश्रय स्थल है। फेस्टिवल में आने वाले अतिथियों को पक्षियों को देखने एवं अनुभव कराने की आयोजकों ने जबरदस्त व्यवस्था की है। फेस्टिवल को कार्यक्रमों, अनुभवों की सीरीज को प्रदर्शनी के रूप में तैयार किया है। प्राधिकरण के उप-निदेशक (लैंड स्केप)पीयूष कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ- इंडिया के साथ मिलकर काफी लंबा रास्ता तय किया है। उनका कहना है कि प्राधिकरण के पास पक्षियों के लिए धैर्य, हौंसला, उपाय-कुशलता, टीम वर्क दृढ़ता, अनुकूलनशीलता, सतर्कता एवं रचनात्मकता जैसा बहुत कुछ है।

उन्होंने बताया कि संजय वन बर्ड फेस्टिवल प्रकृति के साथ कार्य करने का प्रयास है। डीडीए एवं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ- इंडिया के बड़ी संख्या में इस आयोजन में भाग लेंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ- इंडिया के सीईओ करण भल्ला ने बताया शहर के बीचों बीच स्थित संजय वन को 'लर्निंग विद नेचर' का हब बनाने की योजना है। पक्षी प्रेमियों के लिए नेचर ट्रेल, पक्षी आधारित कला एवं शिल्प, इंटरएक्टिव मल्टी मीडिया प्रदर्शनी, वर्कशॉप प्रमुख केंद्र होंगे। फेस्टिवल रविवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भाग ले सकते हैं।

THE HINDU Saturday, March 4, 2023 DELHI

Home Ministry allots ₹120 crore to build fourth prison in Delhi

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Ministry of Home Affairs (MHA) has allocated ₹120 crore to build a fourth jail in the Capital, which will come up in Narela and hold high-risk prisoners, officials said on Friday.

Funds will also be sought for the project from the Delhi government in its upcoming budget. Currently, the city has three prison complexes in Tihar, Rohini and Mandoli.

According to a Delhi government official, the Delhi Development Authority has allotted land for the upcoming prison complex comprising 200-250 cells. It will house high-profile and high-risk prisoners, i.e. those arrested for committing offences against the State and considered a threat to society, from Delhi and neighbouring regions, the official added.

The prison will be equipped with CCTV cameras, as well as high walls, mobile jammers and isolation rooms, he said.

अमर उजाला
नई दिल्ली | शनिवार, 4 मार्च 2023

'संजय वन बर्ड फेस्ट' कल से

कार्यशाला में पक्षी प्रेमियों को मिलेगा 200 से अधिक पक्षियों को देखने का मौका

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पक्षियों वाला प्रदेश है। यहां विभिन्न प्रकार की देशी प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। पक्षी प्रेमी भी इन्हें निहारने के लिए आतुर नजर आते हैं। इसी के मद्देनजर डीडीए पांच मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) से मिलकर पहली बार 'संजय वन बर्ड फेस्टिवल' का आयोजन कर रहा है। गौरतलब है कि संजय वन 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसे देखने के लिए पक्षी प्रेमी अक्सर वहां पहुंचते हैं।

डीडीए के अनुसार फेस्टिवल के दौरान दिल्ली के लोगों को पक्षियों को देखने का अनुभव लेने और इसका आनंद उठाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया ने संजय वन बर्ड फेस्टिवल को कार्यक्रमों, अनुभवों की सीरीज और प्रदर्शनी के रूप में तैयार किया है। इस आयोजन से विश्व वन्यजीव दिवस (तीन मार्च) को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लोगों को पक्षियों से सीखने का अवसर मिलेगा। दरअसल उनके पास धैर्य, हौंसला, उपाय-कुशलता, टीमवर्क, दृढ़ता, अनुकूलनशीलता, सतर्कता और रचनात्मकता जैसा बहुत कुछ है। लोग उन्हें देखकर और उनकी गतिविधियों पर गौर करके यह सब सीख सकते हैं।

फेस्टिवल की खासियत

- देशी प्रजाति के साथ-साथ प्रवासी प्रजाति के पक्षियों भी रहेंगे मौजूद
- प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने के लिए आर्टिस्ट वाले स्टाल लगेंगे
- इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया से मिलेगी पक्षियों के बारे में जानकारी
- प्रवासी पक्षियों और प्रवास पर वर्कशॉप का आयोजन होगा
- प्रकृति और वन्य जीवन पर संसाधन और पब्लिकेशन उपलब्ध होंगे

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला | नई दिल्ली | रविवार, 5 मार्च 2023 ----------DATED----------

स्कूलों की फीस में हो सकती है बढ़ोतरी

शिक्षा निदेशालय ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों से फीस बढ़ाने के प्रस्ताव मांगें

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में अप्रैल से स्कूलों में शुरु होने वाले नए सत्र में अभिभावकों को फीस का करंट लग सकता है। दरअसल, सत्र 2023-24 में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी एजेंसी से आवंटित जमीन पर बने स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। स्कूलों को ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव जरूरी दस्तावेजों व वित्तीय रिकॉर्ड के साथ 06 मार्च से 27 मार्च तक भेजने हैं।

फीस बढ़ोतरी की अनुमति नहीं मिलने तक निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते

ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से 06 से 27 मार्च तक भेजने हैं यह प्रस्ताव

शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा निदेशक (प्राइवेट स्कूल ब्रांच) जेय प्रकाश की ओर से फीस संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए निजी स्कूलों को एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल की ओर से मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव नहीं भेजने वाले स्कूलों को फीस बढ़ोतरी की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या दल के माध्यम से स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच की जाएगी। प्रस्ताव के सही और जरूरी पाए जाने पर फीस बढ़ोतरी की अनुमति मिलेगी।

बिना अनुमति फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते स्कूल : स्कूलों को जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक उनके प्रस्ताव पर शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है, तब तक कोई भी फीस वृद्धि न करें। यदि स्कूल फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता, तो वह शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अपनी फीस में वृद्धि नहीं करेगा।

बिना मंजूरी फीस बढ़ाई तो कार्रवाई : शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी के फीस बढ़ाने की शिकायत मिलने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे में स्कूल के खिलाफ अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीडीए से आग्रह कर स्कूल सोसायटी की लीज डीड भी रद की जा सकती है।

नर्सरी, केजी व पहली कक्षा की फीस पहले ही बढ़ी

स्कूलों का शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर कई स्कूलों ने पहले ही फीस में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 10 से 15 फीसदी तक की है। नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले हो चुके हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों ने इन छोटी कक्षाओं के लिए भी मोटी फीस वसूली है। जबकि सत्र अभी अप्रैल में शुरू होना है।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निर्माण में लापरवाही की सीबीआई से शिकायत

नई दिल्ली। मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यूह अपार्टमेंट निर्माण करने वाले विभाग व ठेकेदारों पर जल्द ही गाज गिरेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निर्माण करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का भी आदेश दिया है। इसके बाद ही डीडीए ने सतर्कता जांच की और निर्देश दिया कि इस मामले में अधिकारियों की भूमिका का पता लगाया जाए।

उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित यह सिग्नेचर व्यूह अपार्टमेंट संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो रहा है। इससे इस परिसर में रहने वाले लोगों की जान जोखिम में है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी शिकायत भी दर्ज की है। 2007-2009 में इसका निर्माण किया गया था। परिसर में 336 एचआईजी, एमआईजी फ्लैट है जिसका एलॉटमेंट 2010 व 1011 में किया गया था। लाखों रुपये के इस मल्टीस्टोरी बिल्डिंग महज 10 साल में जर्जर होने लगा है। इसी मामले में डीडीए ने सीबीआई से सभी संबंधितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। शामिल डीडीए अधिकारी और धोखाधड़ी, खतरे में डालने वालों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने को कहा गया है। ब्यूरो

दैनिक भास्कर | नई दिल्ली, रविवार 05 मार्च, 2023 | 09

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निर्माण केस में डीडीए ने दर्ज कराई शिकायत

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

डीडीए ने मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में खामी और कदाचार के आरोपी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जनवरी में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आदेश दिया था।

डीडीए ने मामले में अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए उपराज्यपाल के निर्देशों के बाद सतर्कता जांच भी की थी। डीडीए ने शीर्ष स्तर के भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जिसने मुखर्जी नगर में संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाली। इसके तहत मामले में शामिल डीडीए अधिकारियों, ठेकेदारों बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
5 मार्च, 2023 ▸ रविवार OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में भ्रष्टाचार व गबन की जांच करेगी सीबीआई

एलजी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ डीडीए का एक्शन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कड़ा एक्शन लिया है। प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में भ्रष्टाचार और गबन के आरोपी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। यह कार्रवाई उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर हुई है। दरअसल एलजी ने जनवरी में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में भ्रष्टाचार और गबन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आदेश दिया था। इस मामले में अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए एक विजिलेंस इन्क्वायरी भी की थी। इसमें पता चला कि डीडीए अधिकारियों और बिल्डरों/ठेकेदारों के बीच एक मिलीभगत थी। जिससे डीडीए को भी नुकसान हुआ और सैकड़ों निवासियों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा

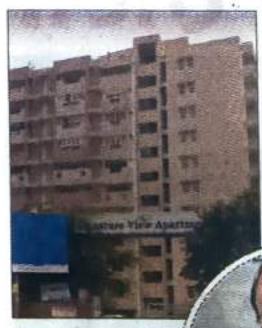

बना। दरअसल, मुखर्जी नगर में बने इस अपार्टमेंट में कई खामियां सामने आयी थीं। मामले पर डीडीए ने टॉप लेवल पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। यहां बता दें कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट 2007-2009 के दौरान बनाया गया था,इस कॉम्प्लेक्स में 336 एचआईजी/एमआईजी फ्लैट हैं। इसे 2011-2012 में निवासियों को आवंटित किया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह इमारत जर्जर हो गई और इसमें लोगों का रहना असुरक्षित बताया गया। वहीं डीडीए के निर्देश पर भी आईआईटी दिल्ली द्वारा 2021-2022 के बीच एक स्टडी की गई जिसमें इमारत को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया गया था, जिसे तुरंत 'खाली करने और डे मो लि श करने' की सिफारिश की गई थी। इस बारे में एलजी ने 24 जनवरी को आदेश दिया था कि ठेकेदारों/बिल्डरों/निर्माण एजेंसियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्माण में चूक और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार सभी डीडीए अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए थे। इसके बाद डीडीए ने मैसर्स विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जैसे ठेकेदारों सहित सभी संबंधित टेस्टिंग एजेंसियों मैसर्स भारत टेस्ट हाउस और मेसर्स दिल्ली टेस्ट हाउस, इसमें शामिल सभी डीडीए अधिकारियों और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जीवन को खतरे में डालने और दूसरों की सार्वजनिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सीबीआई से एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। इसमें दोषी डीडीए अधिकारी जिनमें तीन सदस्य (इंजीनियरिंग), छह मुख्य अभियंता, नौ अधीक्षण अभियंता, नौ कार्यकारी अभियंता, चार सहायक अभियंता और आठ कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।

millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 5 MARCH, 2

DDA lodges complaint with CBI over 'lapses' in Signature View Apartments construction

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The DDA has lodged a complaint with the CBI against officials and contractors accused of "lapses and misconduct" in the construction of the Signature View Apartments in North Delhi's Mukherjee Nagar, Raj Niwas officials said on Saturday. Lt Governor V K Saxena in January ordered criminal proceedings against errant officials. The DDA also conducted a vigilance inquiry, following the Lt Governor's directions, to ascertain the role of officials in the case.

"In a massive crackdown against 'corruption and negligence' at the top level that has put hundreds of lives at risk in the structurally damaged Signature View Apartments in Mukherjee Nagar, the DDA (Delhi Development Authority), following directions of the Lt Governor, has lodged a complaint with the CBI to lodge FIR against the erring DDA officials, contractors/builders involved in the case," an official said. Built in 2007 2009, the complex comprises 336 HIG/MIG flats.

In January, Saxena ordered the "immediate initiation of criminal proceedings against the contractors/builders/construction agencies and a vigilance inquiry to identify all DDA officials responsible for lapses/misconduct in the construction of the said buildings and subsequent criminal action against the defaulting officials".

"The DDA has requested the CBI to register FIR against 'all concerned including the contractors namely M/s Winner Construction Pvt Ltd and M/s Grover Construction Pvt Ltd, the testing agencies — M/s Bharat Test House and M/S Delhi Test House, all involved DDA officials and unknown persons' for offences of cheating, criminal breach of trust, endangering life and public safety of others and other relevant provisions of Prevention of Corruption Act," the official said.

The erring DDA officials include three engineers, six chief engineers, nine superintending engineers, nine executive engineers, four assistant engineers and eight junior engineers during the period, he added.

"The vigilance inquiry has established 'collusion' between the DDA officials and builders/contractors that resulted in 'compromising the quality and structural safety requirement during the construction', thereby causing wrongful loss to DDA besides putting to peril the lives and property of hundreds of residents," the official said.

It found that the provisions on quality control, as highlighted in the contract and the Central Public Works Department manual, were bypassed. As a result, the construction failed in less than a decade of the building's erection.

"It also found that the concrete in the structure is, at most locations, of a lower grade than that expected. Despite several repairs of the existing structure, the structural stability continues to fail to an extent that an independent expert has suggested immediate evacuation of the buildings. "It was the duty of the contractor and all the concerned officers to ensure that prescribed norms of quality control and terms and conditions of the agreement are followed. It appears that either the officers had failed to point the deficiencies during the construction or effectively colluded with the agency to compromise the quality and provide wrongful gains to the agency," the report noted.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। रविवार • 5 मार्च • 2023 राष्ट्रीय सहारा
NAM DATED

डीडीए ने 'खामी व कदाचार' को लेकर सीबीआई से की शिकायत

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण का मामला

- डीडीए ने अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सीबीआई में दर्ज कराई है शिकायत, मुखर्जी नगर में है यह अपार्टमेंट
- एलजी सक्सेना ने जनवरी में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आदेश दिया था
- एलजी के निर्देशों के बाद डीडीए ने अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए सतर्कता जांच की थी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में खामी को लेकर अपने अधिकारियों, निर्माण एवं जांच एजेंसियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सीबीआई में शिकायत दी है। प्राधिकरण के शिकायती पत्र के मुताबिक निर्माण कंपनी मैसर्स विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जांच एजेंसी मेसर्स भारत टेस्ट हाउस एवं मेसर्स दिल्ली टेस्ट हाउस के अलावा डीडीए के अधिकारियों में तीन अभियंता, छह मुख्य अभियंता, नौ अधीक्षण अभियंता, नौ कार्यकारी अभियंता, चार सहायक अभियंता एवं आठ कनिष्ठ अभियंता (करीब 40 अधिकारी) शामिल बताए जाते हैं। इसकी पुष्टि राजनिवास के सूत्रों ने की है।

एक अधिकारी ने कहा, "डीडीए ने शीर्ष स्तर के 'भ्रष्टाचार और लापरवाही' के खिलाफ उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जिसने मुखर्जी नगर में संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाली। इसके तहत मामले में शामिल डीडीए अधिकारियों, ठेकेदारों/ बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई है।" यहां 2007-2009 में निर्मित परिसर में 336 एचआईजी/एमआईजी फ्लैट शामिल हैं।

जनवरी में सक्सेना ने 'ठेकेदारों/बिल्डरों/निर्माण एजेंसियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की तत्काल शुरुआत करने और उक्त भवनों के निर्माण में चूक/कदाचार के लिए जिम्मेदार डीडीए अधिकारियों की पहचान करने और बाद में चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया।' अधिकारी ने कहा, "डीडीए ने सीबीआई से अनुरोध किया है कि ठेकेदारों 'मैसर्स विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, परीक्षण एजेंसियों - मेसर्स भारत टेस्ट हाउस और मेसर्स दिल्ली टेस्ट हाउस, डीडीए के सभी संबंधित अधिकारियों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जीवन को खतरे में डालने और दूसरों की सार्वजनिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।" उन्होंने कहा कि आरोपी डीडीए अधिकारियों में इस अवधि के दौरान तीन अभियंता, छह मुख्य अभियंता, नौ अधीक्षण अभियंता, नौ कार्यकारी अभियंता, चार सहायक अभियंता और आठ कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, "सतर्कता जांच से यह बात सामने आई है कि डीडीए अधिकारियों और बिल्डरों या ठेकेदारों के बीच 'मिलीभगत' की गई, जिसके परिणामस्वरूप 'निर्माण के दौरान गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा से समझौता' किया गया, जिससे डीडीए को नुकसान हुआ और सैकड़ों निवासियों की जान और संपत्ति को नुकसान पहुंचा।" रिपोर्ट में कहा गया यह पाया गया कि अनुबंध और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमावली में उल्लिखित गुणवत्ता नियंत्रण के प्रावधानों को दरकिनार किया गया। नतीजतन, भवन के निर्माण के एक दशक से भी कम समय में निर्माण विफल हो गया। रिपोर्ट में कहा गया, "यह भी पाया गया कि संरचना में कंक्रीट अधिकांश स्थानों पर अपेक्षा से कम ग्रेड की है। मौजूदा संरचना की कई मरम्मत के बावजूद संरचनात्मक स्थिरता इस हद तक विफल रही है कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने इमारत को तत्काल खाली कराए जाने की बात कही है।"

वर्ष 2011-2012 में निवासियों को आवंटित इमारत में शीघ्र ही निर्माण संबंधी मुद्दे सामने आने लगे, जिससे निवासियों को डीडीए से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डीडीए के कहने पर आईआईटी-दिल्ली द्वारा 2021-2022 में किए गए एक अध्ययन में इमारत को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया गया। अध्ययन में इमारत को तुरंत 'खाली करने और तोड़े' जाने की सिफारिश भी की गई। उपराज्यपाल ने डीडीए को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के परामर्श से परिसर के लिए एक पुनर्विकास और पुनर्वास योजना तैयार करने का आदेश दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | MARCH 5, 2023
----------DATED----------

DDA urges CBI to probe lapses in Signature View Apartments' construction

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Central Bureau of Investigation (CBI) is likely to probe the role of 39 Delhi Development Authority (DDA) officials and contractors in connection with the poor quality of construction of Signature View Apartments in Mukherjee Nagar in North Delhi.

Following Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena's directions, the DDA lodged a complaint with the CBI to register FIR against all concerned for endangering the lives of residents and for criminal breach of trust.

The DDA also conducted a vigilance enquiry, following the Lt Governor's directions, to ascertain the role of officials in the case.

"In a massive crackdown against 'corruption and negligence' at the top level that has put hundreds of lives at risk in the structurally damaged Signature View Apartments in Mukherjee Nagar, the DDA, following directions of the LG, has lodged a complaint with the CBI to lodge FIR against the erring DDA officials, contractors/builders involved in the case," an official said.

Built in 2007-2009, the complex comprises 336 HIG/MIG flats. In January, Saxena ordered the "immediate initiation of criminal proceedings against the contractors/builders/construction agencies and a vigilance enquiry to identify all DDA officials responsible for lapses/misconduct in the construction of the said buildings and subsequent criminal action against the defaulting officials".

The erring DDA officials include three engineers, six chief engineers, nine superintending engineers, nine executive engineers, four assistant engineers and eight junior engineers during the period, he added.

"The vigilance enquiry has established 'collusion' between the DDA officials and builders/contractors that resulted in 'compromising the quality and structural safety requirement during the construction', thereby causing wrongful loss to DDA besides putting to peril the lives and property of hundreds of residents," the official said.

Continued on Page 2

DDA urges CBI to probe...

From Page 1

"The DDA has requested the CBI to register FIR against 'all concerned, including the contractors namely M/s Winner Construction Pvt Ltd and M/s Grover Construction Pvt Ltd, the testing agencies — M/s Bharat Test House and M/S Delhi Test House, all involved DDA officials and unknown persons' for offences of cheating, criminal breach of trust, endangering life and public safety of others and other relevant provisions of Prevention of Corruption Act," the official said.

It found that the provisions on quality control, as highlighted in the contract and the Central Public Works Department manual, were bypassed. As a result, the construction failed in less than a decade of the building's erection.

"It also found that the concrete in the structure is, at most locations, of a lower grade than that expected. Despite several repairs of the existing structure, the structural stability continues to fail to an extent that an independent expert has suggested immediate evacuation of the buildings.

"It was the duty of the contractor and all the concerned officers to ensure that prescribed norms of quality control and terms and conditions of the agreement are followed. It appears that either the officers had failed to point out the deficiencies during the construction or effectively colluded with the agency to compromise the quality and provide wrongful gains to the agency," the report noted.

Allotted to residents in 2011-2012, the building started displaying construction related issues shortly afterwards, forcing the residents to approach the DDA. A 2021-2022 study by IIT-Delhi at the behest of DDA found the building to be structurally unsafe. The study also recommended to immediately 'vacate and dismantle' the building.

The LG has ordered the DDA to draw up a redevelopment and rehabilitation plan for the complex in consultation with the Residents' Welfare Association.

राष्ट्रीय सहारा

दिल्ली में 20 साल की जगह 10 साल का बने मास्टर प्लान : सीटीआई

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी है। अब इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी मिलती है, तो दिल्ली में कई तरह के बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट और मास्टर प्लान 2021 में अब तक हुए कार्यों पर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने सवाल उठाए हैं। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा है कि दिल्ली में मास्टर प्लान 20 साल का बनता है, जो कि एक लंबी अवधि है। ये अधिकतम 10 साल का होना चाहिए।

■ 20 साल में बदल जाती हैं दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियां : सीटीआई

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। मास्टर प्लान 2021 में की गई तमाम घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। 20 साल के लंबे अंतराल में नेता और जिम्मेदार अधिकारी इधर-उधर हो जाते हैं। किसी की जवाबदेही नहीं बनती है। प्लान पर ठीक से काम नहीं हो पाता। बृजेश गोयल ने बताया कि इस संदर्भ में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को सीटीआई ने एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 10 साल का हो, भले विजन 20 साल का हो सकता है। आज से 20 साल बाद दिल्ली की स्थिति कैसी होगी, कोई नहीं जानता। अधिकारी योजनाओं को फॉलो तक नहीं कर पाते, डेवलेपमेंट प्लान को लागू करने में तकनीकि दिक्कतें आती हैं।

सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 में तमाम प्लानिंग अब तक अधूरी है। बाजारों के पुनर्विकास पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। व्यापारियों को अलग से गोदाम मुहैया कराने थे, ये काम रुका हुआ है, सर्कल रेट की दिक्कतें बरकरार हैं, कहीं 10 गुना ज्यादा रेट हैं, तो कहीं काफी कम हैं। सीलिंग की समस्या का समाधान नहीं निकला, आज भी दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस भेजे जाते हैं। सदर बाजार में पिछले दिनों दुकानें तक सील कर दी गईं। प्लानिंग थी कि आम माफी योजना के जरिए सीलिंग की समस्या का निपटारा करेंगे। पुराने मास्टर प्लान में कई बाजारों को शिफ्ट करना था जो कि अधूरा पड़ा है, लैंड पूलिंग प्रक्रिया अधूरी है। बृजेश गोयल ने कहा कि अब व्यापारियों में संशय है कि मास्टर प्लान 2041 की योजनाओं पर कितना और कैसे काम हो पाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- THE HINDU ----------------DATE Monday, March 6, 2023 DELHI

Landowners who formed the first consortium rue lack of roads

Muneef Khan
NEW DELHI

Landowners of Sector 8-B in north-west Delhi, who became the first to form a consortium under Delhi Development Authority's Land Pooling Policy (LPP), say a big obstacle they're facing, in terms of attracting real-estate developers to the area, is the lack of connectivity.

"We have been able to pool 100 acres, where around 5,000 flats could be built. However, the developers will get attracted to invest here only if they see some promise in the form of roads," said Dinesh Rana, a landowner who heads the consortium here.

Sector 8-B comprises two villages – Gadi Khasro and Ibrahimpur, located 20 km from central Delhi.

These villages are among the 105 identified by the urban body under the LPP. The policy allows forming of a consortium that can collaborate with a developer entity or plan the development on its own after surrendering 40% of the pooled land to the DDA for public infrastructure works.

To form a consortium, at least 70% of landowners have to agree to pool in their land and 70% of the land needs to be contiguous.

However, these two eligibility conditions created roadblocks for the DDA in implementing the LPP, which was notified twice – in 2013 and 2018.

To overcome the roadblocks, Union Minister for Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri, in March 2022, announced that conditional notices to form consortiums would be issued to landowners who have expressed interest in the policy, provided they can convince the remaining landowners to pool in their land within a stipulated time. The landowners of Sector 8-B were among those who received a provisional notice. Earlier this week, they became the first to meet both the conditions needed to form a consortium.

Groundbreaking move

Landowners in Gadi Khasro and Ibrahimpur, located 20 km from central Delhi, have formed a consortium under the Land Pooling Policy

- Total land available for pooling - **120 acres***
- Land pooled under LPP - **100 acres***
- Estimated number of flats that can be built in the sector - **5,000***
- Nearest metro station - Samaypur Badli **(11 km)**

*figures provided by the consortium

Land at Gadi Khasro village, which is part of LPP's Sector 8-B. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

Connectivity issues

The nearest metro stations from Gadi Khasro and Ibrahimpur are Samaypur Badli (11 km) and Majlis Park (15 km). However, the area has schools, hospitals and health centres within a 5 km radius, all located near Burari. Currently, most of the land in these two villages is used for agriculture, primarily to cultivate paddy and wheat.

"None of the roads meant to be laid here, as per the Master Plan for Delhi-2021, have been built. This has resulted in a steady flow of encroachments in the form of unauthorised constructions. This will affect the connectivity between the sectors," said Mr. Rana.

Jamuna Dutt, another landowner in the sector, also said that the DDA must improve connectivity in the area.

Most landowners, who are part of the consortium, believe that the solution to the pending development can be addressed only through proposed amendments to the Delhi Development Act, announced by Mr. Puri last year.

One of the proposed amendments makes land pooling mandatory for the remaining landowners if the minimum participation rate of 70% is achieved. The other amendment grants power to the Centre to declare land pooling mandatory, even if the minimum criteria of 70% participation and 70% contiguity are not achieved.

Responding to the landowners' observations, a senior DDA official said that demolition drives have been conducted to remove the unauthorised constructions in the area. More such drives are scheduled over the coming weeks.

"Any development in the 105 villages must be done as per the land pooling policy. As for the roads proposed in the master plan, many land portions do not belong to the DDA, as they are privately owned and are yet to be acquired," the official added.

How pooling works

"The consortium can collaborate with a developer entity or plan the development on its own. First, however, it has to draft and provide us [DDA] with a layout plan, which we will check and approve," said another senior official.

As per the policy, the DDA will issue a provisional development licence upon issuing the approval.

Saxena hosts G-20 envoys on spruced Yamuna floodplains

Delhi Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Sunday hosted envoys of various G20 and other nations at Asita East on the Yamuna river floodplains, which has been restored and rejuvenated by the Delhi Development Authority, Raj Niwas officials said. "Ambassadors and other diplomats of 11 countries visited Asita East and went on a nature trail and bird watching tour along the floodplains," the officials added. The envoys appreciated the rich biodiversity and the efforts undertaken to restore the ecological character of the Yamuna.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | MONDAY | MARCH 6, 2023 ----------DATED----------

Diplomats of 11 nations visit Asita East park on Yamuna floodplain

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

In an effort aimed at showcasing Delhi's natural heritage before the world leaders congregating in the national Capital in run up to the G-20 meet, Lt Governor Vinai Kumar Saxena on Sunday hosted envoys/diplomats of the G-20 and other nations at Asita East on the floodplain of River Yamuna.

It has been restored and rejuvenated by Delhi Development Authority (DDA) in a record time of less than six months. Union Minister of State for External Affairs, Meenakshi Lekhi was also present on the occasion.

Ambassadors and other diplomats of 11 countries visited Asita East early morning and went on a nature trail and bird watching tour along the floodplains, spotting over 30 species of birds.

Housing varied flora and fauna, including rare migratory birds, the complex has evolved into a paradise for birders, in a short span of time. Diplomats also went cycling through the vast grasslands of Asita East. Considering the eco-sensitive character of the floodplains, the visitors left their vehicles right at the entrance on Vikas Marg and took electric carts to reach the floodplains. Some of the visitors also preferred walking down to the floodplains.

Visibly impressed by the turnaround of this stretch of the Yamuna Floodplains in a record time of less than six months, the foreign diplomats appreciated the rich bio-diversity and the efforts undertaken to restore the ecological character of the Yamuna.

Speaking on the occasion, Saxena lauded the efforts that have gone into rejuvenating the Yamuna Floodplain and exhorted all stakeholders to put in collective efforts in undoing the destruction caused to the natural heritage due to rampant urbanisation.

"Asita has been our own effort at such rejuvenation. Just 6 months back, this fragile riverine eco-system was a dump yard of waste, squatters and stray animals. Persistent efforts by DDA has resulted in salvaging a self- contained eco system that houses rich natural diversity."

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली। सोमवार • 6 मार्च • 2023

एनडीएमसी का जी 20 फ्लावर सीपी में फेस्टिवल 11 से

नई दिल्ली (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) 11 और 12 मार्च को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में जी 20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य जी20 सदस्य और अतिथि देशों की जीवंतता और रंगीन प्रदर्शन को भारत की राजधानी में प्रदर्शित करना है।

गौरतलब है कि नई दिल्ली में कनॉट प्लेस, दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटक, वाणिज्यिक आकर्षण है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक और नागरिक आते हैं। यह फूल उत्सव जी20 सदस्यों और अतिथि देशों के बारे में आम जनता के बीच प्रचार और जागरूकता का एक अवसर है। इसमें विभिन्न रंगों और किस्मों के फूलों के पौधों को विभिन्न रूपों और स्थापनाओं, संरचनाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। एनडीएमसी भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न फूलों के पौधों को प्रदर्शित करेगी।

एनडीएमसी के इस पुष्प महोत्सव में भाग लेने के लिए सभी जी20 सदस्य देशों और अतिथि देशों को आमंत्रित किया गया है। एनडीएमसी सभी भाग लेने वाले जी20 सदस्य देशों और अतिथि देशों को पुष्प महोत्सव के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करेगी। इस फ्लावर फेस्टिवल में जी20 सदस्य देश और अतिथि देश प्रदर्शित करने के लिए फूलों के पौधे और अन्य पौधे लाएंगे। फूलों के पौधे और कोई भी अन्य पौधे गमलों में लगे पौधों की विभिन्न किस्मों को या तो स्थानीय रूप से या उनके देश में उत्पादित हो, वे उन्हें यहां प्रदर्शित कर सकते हैं।

एनडीएमसी के इस फ्लॉवर फेस्टिवल में विभिन्न सरकारी विभागों की भागीदारी भी देखी जाएगी। इनमें बागवानी विभाग, नागरिक एजेंसियां, प्रमुख नर्सरी, वागवानी

■ वनस्पतियों और जीवों की थीम पर स्कूली बच्चों के बीच स्थल पर पेंटिंग प्रतियोगिता भी की जाएगी आयोजित

उपकरण, बीज, उर्वरक आदि के आपूर्तिकर्ता भी शामिल होंगे। मौसमी और विशिष्ट वनस्पतियों की यहां एक विशाल विविधता प्रदर्शित की जाएगी। इस महोत्सव में फूलों के उत्सव के दौरान जी20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के राष्ट्रीय फूलों या प्रमुख फूलों के बगीचों जैसे फूलों की पेंटिंग या तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। फ्लावर फेस्टिवल के दौरान किसी भी फूल, सजावट या फूलों की व्यवस्था का प्रदर्शन भी किया जा सकता है।

वनस्पतियों और जीवों की थीम पर स्कूली बच्चों के बीच स्थल पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। सभी जी-20 सदस्य देशों और अतिथि देशों से अनुरोध है कि वे पुष्प महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते समय उन्हें अपनी रुचि की अभिव्यक्ति को जल्द भेजने का अनुरोध किया गया है, ताकि एनडीएमसी इस पुष्प महोत्सव में प्रतिभागियों को उनकी पुष्प प्रदर्शनी के प्रदर्शन के लिए प्रमुख स्थान आवंटित कर सके। एनडीएमसी के इस फ्लावर फेस्टिवल में जी20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के अलावा, एनडीएमसी ने विभिन्न सरकारी विभागों जैसे सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, जल बोर्ड, नोएडा और गाजियाबाद प्राधिकरण, आईसीएआर और नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के राज्य - भवनों और सदनों को भी आमंत्रित किया है। बागवानी के प्रति उत्साही लोगों के लिए यह पुष्प प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण त्योहार होगा। यहां फ्लावर फेस्टिवल में डहलिया, बोगेनविलिया, पत्तेदार पौधे, बोन्साई, कैक्टस और पॉटेड पौधों में रसीले पौधे, हैंगिंग बास्केट, फ्लोरल फिगर और बोर्ड, ट्रे गार्डन, फ्लोरल अरेंजमेंट्स आदि जैसे रंगीन और जीवंत फूलों के विभिन्न वर्गों को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया जाएगा जो भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता को दर्शाता है। इस पुष्प महोत्सव का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा और प्रवेश कनॉट प्लेस के डी ब्लॉक के सामने वाले गेट से होगा। लोग विभिन्न स्टालों से अपने पसंदीदा पौधे, फूल आदि भी खरीद सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost ▸ 6 मार्च, 2023 ▸ सोमवार -DATED-
MONDAY, 6 MARCH, 2023 | NEW DELHI

TO SHOWCASE VIBRANCY AND COLOURFUL DISPLAY

NDMC's G-20 Flower Fest on Mar 11, 12

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: New Delhi Municipal Council is organising the "G-20 Flower Festival" at Central Park, Connaught Place on March 11 and 12. The objective is to showcase the vibrancy and colourful display of G-20 member and guest countries.

Connaught Place in New Delhi is a major tourist and commercial attraction of Delhi where large numbers of tourists and citizens visit every day, the flower festival is an opportunity for publicity and awareness amongst the general public about G-20 members and guest countries.

The Flower Festival will also witness participation from various govt depts, civic agencies, leading nurseries

Flowers of different colours & varieties will be displayed in the different forms and installations. NDMC will provide required space to all the participating G-20 member countries and guest countries for the flower festival.

The timings of the festival will be from 10 am to 7 pm. The entry will be free for the general public and will be from Gate opposite to D-Block. The public can also purchase their favourite plants, flowers etc from various stalls. NDMC will also arrange musical and cultural programmes on the site at the Central Park Amphitheatre.

The G-20 member countries and guest countries will bring flower plants and any other plants to display during the flower festival. The Flower Festival will also witness the participation from various govt departments, civic agencies, leading nurseries, supplier of horticulture equipment, seeds, fertilisers, etc.

A large variety of seasonal and exclusive flora would be at display. It will also feature paintings and photographs of flowers such as national flowers or major flower gardens of G-20 member countries and guest countries during the Flower festival.

A painting competition will also be organised at the site amongst the school children on the theme of Flora and Fauna.

Apart from G-20 member countries and guest countries, NDMC has also invited the various government departments like CPWD, PWD, MCD, DDA, Jal Board, Noida & Ghaziabad authority, ICAR and State Bhawans and Houses in New Delhi.

G-20: Diplomats of 11 countries visit Asita East park on Yamuna floodplain

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Diplomats of 11 countries visited Asita East, a biodiversity park on the Yamuna floodplain, for a nature trail and birdwatching, officials said on Sunday.

In an effort aimed at showcasing Delhi's natural heritage before the world leaders congregating in the national Capital for various G-20 events, Lieutenant Governor V K Saxena hosted the envoys at Asita East, which has been restored by the Delhi Development Authority (DDA).

Saxena exhorted all stakeholders to put in collective efforts in undoing the destruction caused to the natural heritage due to rampant urbanisation.

"Asita has been our own effort at such rejuvenation. Just six months back, this fragile riverine ecosystem was a dump yard of waste, squatters and stray animals. Persistent efforts by DDA has resulted in salvaging a self-contained ecosystem that houses rich natural diversity.

Delhi Lt Governor VK Saxena addresses envoys

G-20 delegates at the flood plains of the River Yamuna

"Though the Yamuna floodplain remains fragile, efforts are being made to restore and rejuvenate Delhi's natural heritage that is crucial for making Delhi environmentally sustainable with a refurbished green-blue ecosystem," he said.

Ambassadors and other diplomats of 11 countries, including some G-20 member nations, visited Asita East early morning and went on a nature trail and birdwatching tour along the floodplain, spotting more than 30 species of birds, according to a Raj Niwas statement.

India's G-20 Sherpa Amitabh Kant, Minister of State for External Affairs Meenakashi Lekhi and former foreign secretary Harsh Vardhan Shringla were also present.

Housing varied flora and fauna, including rare migratory birds, the complex has evolved into a paradise for birders in a short span of time, it said.

Diplomats also went cycling through the vast grasslands of Asita East. Considering the eco-sensitive character of the floodplain, the visitors left their vehicles right at the entrance on Vikas Marg and took electric carts to reach the floodplain. Some of the visitors also preferred walking to the floodplain, the statement said.

It said the diplomats were visibly impressed by the turnaround of this stretch of the Yamuna floodplain in a record time of less than six months.

Spread over 90 hectares, Asita East has been rejuvenated by restoring natural depressions, creating catchment zones, reviving floodplain forests and grasslands and creating favourable habitats especially for water and terrestrial birds.

The floodplain had degraded into a dumping ground and was largely encroached upon by squatters. However, with the intervention of the Delhi High Court, the squatters were removed and the entire area was reclaimed by the DDA.

पंजाब केसरी
DELHI

एलजी ने असिता में की जी-20 की मेजबानी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को जी-20 बैठक के लिए राजधानी में एकत्र होने वाले विश्व नेताओं के समक्ष दिल्ली की प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यमुना के बाढ़ के मैदानों पर डीडीए द्वारा विकसित असिता में जी-20 और अन्य देशों के दूतों व राजनयिकों की मेजबानी की। इससे डीडीए द्वारा 6 महीने से भी कम समय के रिकॉर्ड समय में एक सार्वजनिक हरित स्थान के रूप में बहाल करते हुए इसका कायाकल्प किया है। 11 देशों के राजदूतों और अन्य राजनयिकों ने सुबह के समय असिता पूर्व का दौरा किया और पक्षियों की 30 से अधिक प्रजातियों को देखा। इस दौरान एलजी ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र को फिर से जीवंत करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की और सभी स्टेक होल्डर्स से बड़े पैमाने पर शहरीकरण के कारण प्राकृतिक विरासत को हुए नुकसान को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। असिता पूर्व में लगभग 2.5 हेक्टेयर आकार की एक पुनर्निर्मित आर्द्रभूमि है जो 60 मिलियन लीटर से अधिक पानी बढ़ा रही है। इसमें केवल छह महीने के रिकॉर्ड समय में फ्लड प्लेन इकोसिस्टम के 4000 देशी पेड़ और लगभग 3.35 मिलियन नदी की घास लगाई गई है। इन सभी ने लगभग 63 किस्मों के निवासी और प्रवासी पक्षियों को इस सर्दी में अपना घर बनाने के लिए आकर्षित किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला ----------DATED---------- नई दिल्ली | सोमवार, 6 मार्च 2023

तैयारी

सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाले उत्सव में जी-20 देशों के प्रतिनिधि भी करेंगे शिरकत

जी-20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन करेगी एनडीएमसी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) 11 और 12 मार्च को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में जी-20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य जी-20 सदस्य और अतिथि देशों की जीवंतता और रंगीन प्रदर्शन को भारत की राजधानी में प्रदर्शित करना है। इस दौरान विभिन्न रंगों और किस्मों के फूलों के पौधों को विभिन्न रूपों और संरचनाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

एनडीएमसी भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न फूलों के पौधों को प्रदर्शित करेगी। एनडीएमसी ने फ्लावर फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सभी जी-20 सदस्य देशों और अतिथि देशों को आमंत्रित किया है। वहीं फेस्टिवल में जी-20 सदस्य देश और अतिथि देश प्रदर्शित करने के लिए फूलों के पौधे और अन्य पौधे लाएंगे। वे गमलों में लगे विभिन्न किस्मों के फूलों के पौधे और कोई भी अन्य पौधे स्थानीय रूप से या अपने यहां उत्पादित होने वाले प्रदर्शित कर सकते है। इस फेस्टिवल में विभिन्न सरकारी विभाग मसलन बागवानी विभाग, नागरिक एजेंसियां, प्रमुख नर्सरी, बागवानी उपकरण, बीज, उर्वरक आदि के आपूर्तिकर्ता भी शामिल होंगे।

वनस्पतियों और जीवों की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन

सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, नोएडा और गाजियाबाद प्राधिकरण, आईसीएआर और नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के भवनों और सदनों को भी आमंत्रित किया है। इस दौरान जी-20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के राष्ट्रीय फूलों या प्रमुख फूलों के बगीचों से संबंधित फूलों की पेंटिंग या तस्वीरें भी दिखाई जाएगी। यही नहीं वनस्पतियों और जीवों की थीम पर स्कूली बच्चों के बीच एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।

यमुना के किनारों की रौनक देखने पहुंचे जी-20 देशों से आए प्रतिनिधि। अमर उजाला

जी-20 देशों के प्रतिनिधियों ने देखी प्राकृतिक विरासत

नई दिल्ली। जी 20 बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधि मंडल दल ने रविवार को यमुना किनारे दिल्ली की प्राकृतिक विरासत देखी। दल के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वी.केसक्सेना, राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित रहे। यमुना के इस बाढ़ क्षेत्र का जीर्णोद्धार और कायाकल्प डीडीए ने छह महीने से कम समय में किया है। इस अवसर पर 11 देशों के राजदूतों और अन्य राजनयिकों ने सुबह-सुबह असिता पूर्व का दौरा किया। साथ ही यहां पक्षी देखे। यहां पर पक्षियों की 30 से अधिक प्रजातियां हैं। इसमें दुर्लभ प्रवासी भी शामिल हैं। ब्यूरो

दैनिक भास्कर

नई दिल्ली, सोमवार 06 मार्च, 2023 | 03

रोहिणी सेक्टर-14 के खेल परिसर में रबराइज्ड ट्रैक का उद्घाटन

ट्रैक का काम दो माह में पूरा होगा पीएम मोदी करेंगे उद्घाटनः गुप्ता

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) द्वारा रविवार को रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-14 के खेल परिसर में रबराइज्ड ट्रैक का उद्घाटन रविवार को पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, विधायक व सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकरण, विजेंद्र गुप्ता ने किया। समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निवासियों द्वारा लंबे समय से इस सुविधा की मांग की जा रही थी। निवासियों के से दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाने में सफल हुए।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि वे रोहिणी के तीव्र विकास व आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए दृढ संकल्पित हैं तथा उनका प्रयास है कि क्षेत्र में सभी आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। रोहिणी खेल परिसर में बने ट्रैकों रबडराइज्ड करना इस दिशा में एक प्रयास है।

उन्होंने कहा कि रोहिणी के लगभग सभी सेक्टरों में डीडीए के सभी पार्कों में बने ट्रेकों को पहले ही रबड युक्त फर्शों का निर्माण डीडीए द्वारा करवाया गया है। वे उन सभी सुविधाओं को रोहिणी में देखना चाहते हैं जो देश व दिल्ली के अन्य भागों में उपलब्ध हैं। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि रोहिणी सेक्टर-7 व 8 की सडको के नवीनीकरण का काम शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सेक्टर-14 रोहिणी स्थित खेल परिसर दिल्ली में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी तरह तीन और खेल परिसर रोहिणी में विकसित किए जा रहे हैं जिनका उद्घाटन जनवरी-2024 में पीएम नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा।

एलजी ने की जी-20 में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की मेजबानी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

रविवार को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए द्वारा यमुना किनारे बनाए असिता ईस्ट में जी20 की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधियों की मेजबानी की, जहां अलग-अलग देशों से आए डेलिगेशन में शामिल कई दूतों और अन्य लोगों ने ईको सिस्टम का भ्रमण किया और इसके साथ-साथ विदेशी प्रवासी पक्षियों को देखा। ये सभी डेलीगेशन जी-20 को लेकर की जा रही तैयारियों को देखा और डीडीए के द्वारा एलजी के मार्गदर्शन में पर्यावरण बहाली के लिए बनाई गई कृत्रिम नदी व ईको सिस्टम में टहलने और पक्षियों को देखने पहुंचे थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 4 मार्च 2023

दिल्ली में कटने वाले पेड़ों के बदले दूसरे राज्यों में लगाए जाएंगे पौधे?

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

भविष्य में विकास कार्यों के लिए काटे जाने वाले पेड़ों के बदले में क्षतिपूर्ति पौधारोपण अन्य राज्यों में हो सकता है। उत्तर रेलवे ने वन विभाग को पेड़ों को काटने की अनुमति के साथ सलाह दी है कि वह इसके एवज में क्षतिपूर्ति पौधे यूपी में लगाए जा सकते हैं। वन विभाग के अधिकारी के अनुसार यह प्रपोजल अभी उत्तर रेलवे को वापस कर दिया गया है। इसमें कुछ कमियां हैं।

उत्तर रेलवे ने बिजवासन टर्मिनल के लिए फरवरी में फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए यह आवेदन किया था। इस प्रपोजल के तहत बिजवासन में भविष्य के ट्रैफिक की जरूरतों को देखते हुए एक पैसेंजर और माल ढुलाई सुविधा भी प्रस्तावित है। इसके लिए डीडीए ने करीब 110 एकड़ की जमीन बिजवान में चिह्नित कर ली है। यह टर्मिनल आईजीआई एयरपोर्ट के पास बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की करीब 6.7 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्जन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस फॉरेस्ट लैंड के डायवर्जन के बदले रेलवे ने सुझाव दिया है कि वह उत्तर प्रदेश के मुजफरनगर और बागपत में क्षतिपूर्ति पौधे लगा सकता है। पिछले साल डीडीए ने भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पत्र लिखकर अपील की थी कि केंद्र सरकार के और कुछ अन्य प्रोजेक्ट के लिए क्षतिपूर्ती पौधों को लगाने के लिए आसपास के राज्यों में अनुमति दी जाए। डीडीए के पास अब क्षतिपूर्ति पेड़ों के लिए जगह नहीं है।

फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने इस मामले पर पिछले साल विचार करने का निर्णय लिया था। पिछले साल हुई मीटिंग के कहा गया था कि कमिटी यह सुझाव दे रही है कि यदि प्रक्षतिपूर्ति पौधे लगाने की जगह न हो या कोई ठोस कारण हो, तो ऐसे मामलों में मंत्रालय हर मामले की गंभीरता को देखकर निर्णय ले सकता है।

दिल्ली में जगह नहीं

- बिजवासन टर्मिनल प्रोजेक्ट के तहत मुज्जफरनगर और बागपत में पौधे लगाने का दिया था सुझाव
- वन विभाग के अधिकारी के अनुसार यह प्रपोजल अभी उत्तर रेलवे को वापस कर दिया गया

संजय वन में कल पहला बर्ड फेस्टिवल

WWF (इंडिया) के साथ मिलकर डीडीए कर रहा है आयोजन

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

इस संडे पांच मार्च को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के साथ मिलकर डीडीए संजय वन में पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान यहां कई मनोरंजक गतिविधियां, नेचर वॉक, वर्कशॉप आदि का आयोजन होगा। यह आयोजन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के उपलक्ष्य पर हो रहा है, जो शुक्रवार 3 मार्च को था।

डीडीए अधिकारियों के अनुसार देश के सभी राज्यों की राजधानियों में दिल्ली पक्षियों के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहां काफी संख्या में पक्षियों की स्थानीय प्रजातियां तो मिलती ही हैं साथ ही सर्दियों और गर्मियों के दौरान विदेशी परिंदे भी नजर आते हैं। संजय वन में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं। डीडीए (लैंडस्केप) के डिप्टी डायरेक्टर पी कुमार के अनुसार डीडीए और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया की पार्टनरशिप को काफी समय हो गया है। डीडीए को उम्मीद है कि इस तरह की पहल के अब रिजल्ट दिखेंगे। उन्होंने कहा कि पक्षियों को देखकर हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इससे पहले हम संजय वन में एक्सपर्ट के साथ ड्रेगनफ्लाई फेस्टिवल व कई अन्य आयोजन कर चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सीओओ करण भल्ला ने कहा कि यहां लोगों को कई प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे।

क्या होगा फेस्टिवल में खास : नेचर वॉक में एक्सपर्ट लोगों को कई ग्रुप्स में लेकर जाएंगे और देशी व विदेशी प्रजातियों के बारे में जानकारी देंगे। यहां पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा।

Hindustan Times NEW DELHI SATURDAY MARCH 04, 2023

DDA, WWF to organise bird fest at Sanjay Van

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) and World Wildlife Fund (WWF)-India will jointly host a bird festival at Sanjay Van on Sunday, officials aware of the matter said on Friday. The festival, they said, will look to highlight the Capital's avian diversity and will consist of activities such as nature trails and workshops.

Sanjay Van, a reserve forest in south Delhi that comes under the jurisdiction of DDA, is home to more than 200 species of birds over the course of the year, according to estimates by experts — apart from Delhi's permanent bird population, a large number of species migrate to the city during the summer or the winter.

WWF-India said it has curated the bird festival as a series of events and experiences, including an exhibition for Delhi residents to experience and celebrate birds in the city, adding that this was an extended commemoration of the World Wildlife Day, which is celebrated on March 3 each year.

"DDA and WWF-India have joined hands to create a hub for 'Learning with Nature' within the heart of the city. It offers the residents of Delhi a unique platform to value Delhi's biodiversity and to be involved in its protection," said Karan Bhalla, COO, WWF-India.

Those looking to attend the festival can register at bit.ly/SanjayVanBirdFestival.

Peush Kumar, deputy director (landscapes), DDA, said, "DDA hopes that the number of initiatives being undertaken shall continue to bear fruit."

{ WETLAND BODY FORMS PANEL }

Probe into govt centre being built on 'dry pond'

Jasjeev Gandhiok
jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

NEW DELHI: Taking cognisance of a complaint by local residents and an NGO alleging that a cultural centre is being built at the site where a village pond (johad) once existed in Budhela in Vikaspuri, the State Wetland Authority of Delhi has written to its grievance committee to look into the matter and take corrective action.

The pond, said to have dried up in 2003, was spread over an area about 1 to 1.5 acres.

The complaint alleges that a Sahitya Kala Parishad (SKP) complex is now being built through the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC) at the site.

Residents alleged that though the this piece of land is demarcated as a pond in the Delhi Development Authority (DDA) records, authorities are going ahead with the project anyway.

The complaint says that, in 2004, the same land was "wrongfully allotted to the Delhi government by DDA, which floated a tender for the construction of the complex in 2021".

"The Wetland Authority of Delhi has received a grievance regarding a pond in Budhela. It is requested that necessary action may be initiated," said the member secretary of the Delhi SWA in a letter dated March 2. HT has seen the letter.

A government official, however said, "There is no involvement of any government department or government employee in any such activity."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MARCH 5, 2023

Nod must to hike fees at pvt schools: DoE

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: For the new academic session, which is scheduled to start on April 1, no private school built on government land will be able to increase its fees without an approval of the directorate of education (DoE).

In a circular, DoE said, "All the head of schools/managers of private unaided recognised schools, allotted land by the land-owning agencies on the condition of seeking prior sanction of director of education for increase in fees, are directed to submit their proposals, if any, for prior sanction of DoE through the website of the directorate."

The fee hike proposal can be submitted online between March 6 and March 27.

"Any incomplete proposal submitted by the schools shall be instantly rejected without any hearing. Further, no manual submission of fee hike proposal by any school shall be considered. The proposals submitted by the schools shall be scrutinised/examined by the director of education through any officer or team authorised on his behalf. All such schools are strictly directed not to increase any fee until the sanction is conveyed to their proposal by DoE," added the circular.

The order from DoE is in compliance with a HC order on January 19, 2016

In case, no proposal is submitted, the school shall not increase its fee for the academic session 2023-24. "Any complaint regarding increase of any fee without such prior approval will be viewed seriously and action shall be taken as per the statutory provisions and directions of the hon'ble high court, including a request to DDA for cancellation of lease deed executed in favour of the defaulter school's society," added the circular.

The order is in compliance with an order dated January 19, 2016 of Delhi High Court. It had directed DoE to ensure the compliance of the terms, if any, in the letter of allotment regarding the increase of the fee by private schools allotted land by DDA and other land-owning agencies.

4 दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2023
दिल्ली जागरण
www.jagran.com

दिल्ली में बनेगी चौथी जेल, रखे जाएंगे खतरनाक कैदी

नरेला में बनाई जाएगी 250 सेल वाली जेल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल की तर्ज पर दिल्ली में 120 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली को जल्द ही नरेला में उच्च जोखिम वाले कैदियों को रखने के लिए चौथी जेल मिलेगी.दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परियोजना के पीछे विचार यह है कि वे कैदी, जो राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों के कारण जेल में हैं, अलग रखे जा सकें। हालांकि तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में यह सुविधा है, लेकिन नया जेल परिसर केवल ऐसे कैदियों को रखने के लिए बनाया जाएगा, जो समाज के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय इस जेल परिसर के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित करेगा।

परियोजना के लिए आगामी बजट में दिल्ली सरकार से भी धन मांगा जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नरेला में जेल के लिए जमीन आवंटित की है। किसी-न-किसी योजना के मुताबिक जेल में 250 सेल होंगे और इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल पर बनाया गया है। अधिकारी के अनुसार, जेल में योग जैसी सुधारात्मक सुविधाएं भी होंगी। एक ऐसी फैक्ट्री भी होगी, जहां कैदी कुछ चीजें भी बना सकेंगे। जेल बनाने का उद्देश्य एक सुधार केंद्र के रूप में काम करना है। यह जेल, भले ही इसमें आतंकियों और गैंगस्टरों को रखा जाएगा, लेकिन इसमें योग जैसी सुविधाएं होंगी। परियोजना शुरुआती चरण में है और केंद्र से धन आने के बाद परियोजना पर काम तेज हो जाएगा।

यह पूछने पर कि क्या नई जेल में अन्य पड़ोसी राज्यों के हाई-प्रोफाइल कैदी भी होंगे, अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकता दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों को रखने की है, लेकिन अगर हमें कोई अनुरोध या कुछ निर्देश मिलते हैं, तो इसका पालन भी करना होगा।

निर्माण के लिए 120 करोड रुपये देगा गृहमंत्रालय, राज्य के खिलाफ किए अपराधों के कारण जेल में बंद कैदी ही रखे जाएंगे

यह होगी सुरक्षा व्यवस्था

जेल की सुरक्षा व्यवसथाओं में सीसीटीवी कैमरे, चौबीसो घटे निगरानी, कैदियो के बीच ज्यादा बातचीत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आइसोलेशन रूम, ऊंची दीवारे और बेहतर तकनीक के मोबाइल जैमर शामिल होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियो को बाहरी दुनिया की भनक तक न लगे।

दिल्ली में हैं अभी तीन जेल परिसर

राष्ट्रीय राजधानी मे अभी तिहाड, रोहिणी और मडोली, तीन जेल परिसर है। तिहाड, जिसे दुनिया के सबसे बडे जेल परिसरो मे से एक माना जाता है, मे नौ केंद्रीय जेल शामिल है। इसमे 5,200 कैदियो को रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान मे इसकी विभिन्न केंद्रीय जेलो मे 13,183 कैदी बद हैं। मंडोली मे छह केंद्रीय जेल हैं। इसकी क्षमता 1,050 है, लेकिन वर्तमान मे 2,037 कैदी वहा रह रहे है। रोहिणी मे केवल एक सेंट्रल जेल है, जिसकी क्षमता 3,776 है, लेकिन वहा 4,355 कैदी बद हैं। इन जेलो मे बद उच्च जोखिम वाले कैदियो मे ओलंपिक रजत पदक विजेता सुशील कुमार, ठग सुकेश चद्रशेखर और कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक शामिल है।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 4 मार्च, 2023

संजय वन में रविवार से बर्ड फेस्टिवल का आगाज

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : राजधानी में रविवार से बर्ड फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। संजय वन में लगने जा रहे इस फेस्टिवल में नेचर वाक, पक्षी आधारित कला और शिल्प, वर्कशाप आदि का आयोजन होगा। इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर - इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया) द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है। शुक्रवार को वन्यजीव दिवस पर इसकी घोषणा की गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उप निदेशक (लैंडस्केप) पीयूष कुमार ने बताया कि प्राधिकरण और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के बीच रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से नागरिकों के बीच प्रकृति आधारित शिक्षा प्रदान करने और पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संजय वन बर्ड फेस्टिवल 'प्रकृति के साथ काम करें, इसके विपरीत नहीं...' का एक प्रयास है। इससे पूर्व भी डीडीए ने संजय वन में वनस्पतियों और जीवों पर आधारित ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कर चुका है।

संजय वन में प्रकृति का आनंद लेने पहुचे पर्यटक ● सौ. आयोजक

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के सीओओ करण भल्ला ने कहा कि डीडीए और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया ने संजय वन में 'लर्निंग विद नेचर' के लिए एक हब बनाने के लिए हाथ मिलाया है। संजय वन में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों को एक साथ इसे देखने के लिए यह एक समृद्ध यात्रा होगी, जिसमें हमारे बीच के अद्भुत प्राकृतिक आवासों को जानने और उनकी रक्षा करने में शहर के सभी उम्र के निवासियों को शामिल किया जाएगा।

फेस्टिवल में खास

नेचर ट्रेल्स : वर्ड वाक के जरिये प्रवासी प्रजातियों को देखने का मौका मिलेगा।

पक्षी आधारित कला और शिल्प : स्टोन पेंटिंग और बाडी आर्ट तक कई प्रकार के स्टाल लगाए जाएंगे।

इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया प्रदर्शन : पक्षियों से संबंधित इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के माध्यम से पक्षियों के बारे में जानेंगे। **खेल-आधारित शिक्षा** के माध्यम से पक्षियों की खोज और बर्डवाचिंग के लिए एक स्टाल भी होगा।

वर्कशाप : एक बर्डवाचर्स के रूप में विशेषज्ञ निखिल देवासर प्रवासी पक्षियों और प्रवास पर दिल्ली की पक्षी विविधता पर एक वर्कशाप का नेतृत्व करेंगे। एक प्रदर्शनी भी लगेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

2 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 5 मार्च, 2023

नए मास्टर प्लान में दिख रहा प्लानिंग का घोर अभाव

दिल्ली का अगले 20 वर्ष का मास्टर प्लान 2041 बनकर तैयार, पुरानी कालोनियों के पुनर्विकास का जिक्र नहीं

संजीव गुप्ता● नई दिल्ली

अगले 20 वर्ष की दिल्ली के लिए नया मास्टर प्लान-2041 तो बन गया, जल्द ही अधिसूचित भी हो जाएगा, लेकिन दो खंड और दस अध्याय में विभक्त इस लंबे-चौडे प्लान में भी विकास को लेकर केवल प्लानिंग ही की गई है। पुरानी कालोनियों के पुनर्विकास का इसमें जिक्र तक नहीं है। नई अनधिकृत कालोनियां न बसें, इसका तो ध्यान रखा गया है, लेकिन पुरानी अनधिकृत कालोनियों का विकास कैसे किया जाए, इसे लेकर कारगर प्लानिंग का अभाव खटकता है। ऐसा न होने की सूरत में राष्ट्रीय राजधानी का चहुंमुखी विकास कतई संभव नहीं हो सकता।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी संवेदनशील है दिल्ली : राजधानी की नियमित कालोनियों में बिल्डर फ्लैट के चलन से भी आबादी कई गुणा बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने व सुविधाएं सीमित रहने की वजह से सिस्मिक जोन-4 में शामिल दिल्ली प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील हो रही है। समस्या को दूर करने के लिए राजधानी में कई स्तरों पर प्लानिंग हुई है, री-डेवलपमेंट प्लान भी बने, लेकिन

पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के समीप किनारी बाजार, जहां घनी आबादी के साथ जर्जर भवन कभी भी हादसे को दे सकते हैं दावत ● चंद्र प्रकाश मिश्र

सिरे नहीं चढ़ सके। इसका सबसे बड़ा उंदाहरण लैंड पुलिंग नीति है, जिसके तहत अब तक एक भी सेक्टर फाइनल नहीं हो पाया है।

कारगर साबित नहीं हुई लैंड पुलिंग नीति : अधिकारियों के अनुसार लैंड पुलिंग नीति वर्ष 2018 में अधिसूचित हुई थी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सकी है। इसकी दो सबसे बड़ी बाधाएं यह हैं कि इसमें 70 प्रतिशत भू-स्वामियों का एकसाथ आना और 70 प्रतिशत जमीन एकसाथ मिलना जरूरी है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में एफएआर बढ़ाकर पुरानी बिल्डिंगों को री-डेवलप करने का प्लान है। इन कालोनियों में ऊंची इमारतें बनेंगी। बची जगहों पर जनसुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यहां पार्किंग, सड़कें, स्वास्थ्य सेवा, पार्क आदि के लिए जगह रहेगी। अगस्त 2022 में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी री-डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम-1957 में बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसे मंजूरी मितली है तो बड़ी अड़चन दूर हो जाएगी।

आमजन का दर्द: पूर्वी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एक्टेंशन की कुछ हाउसिंग सोसायटी 70 और 80 के दशक में बनी थी। इन्हें री-डेवलपमेंट की जरूरत है। लोगों ने इसकी कोशिशें भी कीं, लेकिन सफल नहीं हुए। आरडब्ल्यूए संगठन ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल के अनुसार चार-पांच दशक पुरानी कालोनियों का री-डेवलपमेंट प्लान जरूरी है । डीडीए को लोगों के साथ मिलकर नियम बनाने होंगे।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग) एके जैन बताते हैं कि नियम तो कई हैं, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल हो रहा है। राजधानी की 50 प्रतिशत से अधिक बिल्डिंग लेआउट प्लान के अनुरूप नहीं हैं। गांवों में कोई रोकटोक नहीं है। वर्ष 2007 में एक समिति बनी थी, जिसने 80 प्रतिशत बिल्डिंग असुरक्षित बताई। डीडीए फ्लैट्स में भी काफी अधिक बदलाव हो रहे हैं। भवन उपनियम सख्ती से लागू हो नहीं पाते। जैन बताते हैं कि उन्होंने सुझाव दिया था कि गांव, पुरानी दिल्ली, अनधिकृत कालोनियों में 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंगों के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए। इनमें यदि रेट्रो-फिटिंग की जरूरत होती है, तो उसे सरकार सब्सिडाइज रेट पर करे, ताकि लोगों पर बहुत अधिक बोझ न आए। इसके लिए पहले लोगों को छह महीने का समय दिया गया, फिर एक वर्ष का, उसके बाद दो वर्ष का और अंत में यह रद ही हो गया। यदि री-डेवलमेंट की बात की जाए, तो इसे न्यायाक प्रक्रिया में लाना होगा, ताकि राजनेताओं की दखलअंदाजी कम हो। वहीं, डीडीए के पूर्व योजना आयुक्त सब्यसाची दास ने बताया कि डीडीए एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं, वे काफी पहले हो जाने चाहिए थे। यह री-डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। लेकिन, हम पहले ही इसमें लगभग दस वर्ष विलंब से चल रहे हैं। इन बदलावों के बिना पुनर्विकास की कोई भी योजना सिरे नहीं चढ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन आज सबसे बड़ी समस्या है। लोग पुनर्विकास में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए अनधिकृत और पुराने बसे इलाकों के हालात बदतर हो रहे हैं। राजधानी में लोग वर्षों से एक ही जगह रह रहे होते हैं। वहां से उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और यह उनकी कमाई का जरिया भी होता है। इसलिए सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते।

इसलिए जरूरी है पुनर्विकास

राजधानी की घनी आबादी वाली कालोनियों में इस समय बिल्डर फ्लैट का चलन तेजी से फल-फूल रहा है। 50 से 200 गज जमीन पर भी चार मंजिल की इमारत में ये लोग कई फ्लैट बना देते हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लैट का न लेआउट प्लन होता है, न गुणवत्ता जांच होती है। यह भूकंपरोधी हैं या नहीं, इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं रहती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED-- दिल्ली जागरण

डीडीए के 39 अधिकारियों की सीबीआइ में शिकायत

नई दिल्ली : मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में हुई अनियमितता के मामले में डीडीए ने अपने 39 अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों की सीबीआइ में शिकायत कर इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। ● पेज 3

डीडीए के 39 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआइ में शिकायत

एलजी के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में हुई अनियमितता के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने 39 अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों की सीबीआइ में शिकायत कर इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने डीडीए के उपाध्यक्ष को 24 जनवरी को मामले में जांच कर आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

वीके सक्सेना ●

वर्ष 2007-2009 के दौरान निर्मित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट परिसर में वर्ष 2011-2012 में फ्लैट आवंटित किए गए थे। इसके तुरंत बाद फ्लैटों में निर्माण संबंधी समस्याएं आने लगी थीं। यहां के निवासियों ने इस संबंध में डीडीए से शिकायत की। पहले अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में आइआइटी दिल्ली से जांच कराई गई। वर्ष 2021-

- सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निर्माण में अनियमितता पर की शिकायत
- आवंटन के बाद ही फ्लैटों में आने लगी थीं निर्माण संबंधी समस्याएं

2022 में दी गई रिपोर्ट में इमारत को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया गया था। इसे तुरंत खाली करने व तोड़ने की सिफारिश की गई थी। इस परिसर में 336 एचआइजी व एमआइजी फ्लैट हैं।

सतर्कता जांच में मिली है कमी: एलजी के आदेश के बाद डीडीए ने सतर्कता जांच कराई, तो सामने आया कि डीडीए अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठगांठ से निर्माण में गुणवत्ता व संरचनात्मक सुरक्षा से समझौता किया गया। अनुबंध और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की नियमावली में तय गुणवत्ता नियंत्रण के प्रविधानों को दरकिनार किया गया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। यही कारण है कि निर्माण के तीन-चार वर्ष में ही इमारत जर्जर होने लगी।

सख्त कार्रवाई » संपादकीय

अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप

डीडीए ने अपनी शिकायत में सीबीआइ से मैसर्स विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ परीक्षण एजेंसी मैसर्स भारत टेस्ट हाउस और मैसर्स दिल्ली टेस्ट के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। अनियमितता में शामिल डीडीए ने इस अवधि के दौरान इस प्रोजेक्ट से जुड़े तीन सदस्य (इंजीनियरिंग), छह मुख्य अभियता, नौ अधीक्षण अभियता, नौ कार्यकारी अभियंता, चार सहायक अभियंता, आठ कनिष्ठ अभियंताओं और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जीवन को खतरे में डालने व सार्वजनिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्य प्रविधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

सांसद खेल प्रतियोगिता से छिपी प्रतिभा को मिल रहा मौका : डा. हर्षवर्धन

जासं., नई दिल्ली: चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत महर्षि दयानंद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पार्क केशवपुरम में बैडमिंटन टूर्नामेंट और कम्युनिटी सेंटर चमेलियान रोड पर कैरम प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डा. हर्षवर्धन ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ समय बिताया और उनके अनुभव साझा किए।

पहले दिन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अलग-अलग आयु वर्ग की 95 टीमों के करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया और कैरम बोर्ड प्रतियोगिता

- पूर्व केंद्रीय मंत्री व चांदनी चौक के सांसद ने बैडमिंटन व कैरम समेत अन्य खेल प्रतियोगिता का किया उद्घाटन

डा. हर्षवर्धन ●

में अगले तीन दिन में करीब 128 खिलाड़ी भाग लेंगे। डा. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रतियोगिता में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों का बढ़ चढ़कर भाग लेना भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। बैडमिंटन नियमित खेलने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला खेल भी है। चांदनी चौक लोकसभा में बैडमिंटन के अलावा कैरम बोर्ड प्रतियोगिता, रस्सा खींच व रस्सा टापने की प्रतियोगिता भी अलग-अलग स्थान पर शुरू हुई, जो अगले तीन दिन तक चलेगी। केशवपुरम के जिला अध्यक्ष राज कुमार भाटिया व चांदनी चौक जिले के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह के साथ ही पूर्व विधायक डा. महेंद्र नागपाल, निगम पार्षद योगेश वर्मा, पूर्व निगम पार्षद तिलकराम गुप्ता समेत भाजपा के जिला व मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 5 मार्च 2023 ERS----------DATED----------

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के घटिया निर्माण का दोषी कौन? CBI करेगी जांच

अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ उपराज्यपाल के निर्देश पर DDA ने CBI में दी शिकायत

मुखर्जी नगर का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट 2007-09 में बना, 2011-12 में अलॉट हुआ

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ अब सीबीआई जांच करेगी। एलजी के निर्देश के बाद डीडीए ने सीबीआई में इस मामले की शिकायत की है। अभी तक जांच के दायरे में उस समय के डीडीए के तीन मेंबर्स (इंजीनियरिंग), 6 चीफ इंजीनियर, 9 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, 9 एजीक्यूटिव इंजीनियर, 4 असिस्टेंट इंजीनियर और 8 जूनियर इंजीनियर हैं।

मुखर्जी नगर में बना सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर काफी कमजोर है। जिसकी लोग शुरुआत से शिकायत करते रहे हैं। यह अपार्टमेंट 2007-09 में बना था। इसके बाद 2011-12 में यह लोगों को अलॉट किया गया। कुछ ही समय बाद इस अपार्टमेंट को असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस अपार्टमेंट में 336 एचआईजी और एमआईजी के फ्लैट्स हैं। इस पर एलजी ने संज्ञान लेते हुए 24 जनवरी को निर्देश दिया था कि लापरवाह अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टरों, बिल्डरों और कंस्ट्रक्शन एजेंसी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाए जाएं और भ्रष्टाचार की जांच की जाए।

अब डीडीए ने इस मामले में सीबीआई में शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। अपनी शिकायत में डीडीए ने कॉन्ट्रैक्टर विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, टेस्टिंग एजेंसी भारत टेस्ट हाउस और दिल्ली टेस्ट हाउस के साथ डीडीए के विभिन्न अधिकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की अपील की है। 2021-22 में आईआईटी दिल्ली ने एक स्टडी की, जिसमें इस अपार्टमेंट को असुरक्षित करार दिया गया और इसे तुरंत खाली करवाकर जमींदोज करने की सलाह दी गई। एलजी ने इस मामले में डीडीए को अपार्टमेंट का रीडिवेलपमेंट और लोगों के पुनर्वास का प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं।

डीडीए ने विजिलेंस जांच में कहा

- कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्वॉलिटी कंट्रोल के नियमों का उल्लंघन किया गया
- निर्माण में शामिल कंक्रीट घटिया क्वॉलिटी की पाई गई है, कुछ मेंटिनेंस वर्क के बाद भी इस बिल्डिंग में खामियां बरकरार हैं
- कॉन्ट्रैक्टर और संबंधित अधिकारियों की यह ड्यूटी है कि वह नियमों का पालन करवाएं, इस प्रोजेक्ट में उनकी लापरवाही सामने आई

संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 5 मार्च 2023

बढ़ सकती है फीस, प्राइवेट स्कूलों से मांगे शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

प्राइवेट स्कूल नए अकैडमिक सेशन में फीस बढ़ाने के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय को अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। निदेशालय ने कहा है कि 2023-24 सेशन की फीस बढ़ाने के लिए एजुकेशन डायरेक्टर की मंजूरी के लिए प्राइवेट स्कूल के हेड/ मैनेजर अपना प्रपोजल 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ऑनलाइन (edudel.nic.in) भेज सकते हैं। ये वो स्कूल हैं जो सरकार की ओर से अलॉट की गई जमीन पर बने हैं। बिना इजाजत ये प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि ऐसे करने पर स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही, डीडीए को डिफॉल्टर स्कूल की सोसायटी को लीज डीड कैंसल करने का अनुरोध किया जाएगा।

फीस बढ़ाने की मंज़ूरी ज़रूरी

शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि स्कूलों को सभी डॉक्युमेंट्स, फाइनैंशल रिकॉर्ड अपने प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा। अधूरे प्रस्ताव बिना रद्द कर दिए जाएंगे। एजुकेशन डायरेक्टर किसी अधिकारी या टीम के जरिए सभी प्रस्ताव की स्क्रूटनी करवाएंगे। अगर स्कूल फीस बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं देता है, तो वो इस सेशन के लिए फीस भी बढ़ा नहीं सकता। अगर बिना इजाजत फीस बढ़ाने की शिकायत आती है तो नियम और हाई कोर्ट के फैसले के तहत ऐसे स्कूलों पर एक्शन लिया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, रविवार, 5 मार्च 2023 ----------DATED----------

10 वर्ष में ही डीडीए फ्लैट की हालत जर्जर हो गई, जांच में भी पाई गई थी अनियमितता

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निर्माण में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी

कलंक के खिलाफ

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। मुखर्जी नगर में डीडीए की ओर से बनाए गए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी। इसको लेकर उपराज्यपाल के आदेश पर डीडीए ने सीबीआई को पत्र लिखा है। गड़बड़ी में डीडीए के अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका को लेकर छानबीन करने की मांग की है। यह फ्लैट महज 10 वर्षों में ही पूरी तरह से खराब हो चुके हैं।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को 2007-09 के बीच डीडीए ने ठेकेदार से बनवाया था। 2011-12 में यहां 336 एमआईजी और एचआईजी फ्लैट आवंटित किए गए। लेकिन निर्माण की गुणवत्ता खराब होने के चलते दो से तीन वर्ष बाद ही फ्लैट की हालत जर्जर होने लगी। इसे लेकर यहां रहने वाले लोगों ने उपराज्यपाल से शिकायत की थी। उपराज्यपाल सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि 2021-22 में आईआईटी से जांच करवाई गई। इसमें अपार्टमेंट की इमारत असुरक्षित पाया गया। उपराज्यपाल ने डीडीए को इमारत तोड़कर उसे दोबारा बनाने के निर्देश दिए। बीती 24 जनवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को विजिलेंस जांच करने के साथ ही इस मामले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आपराधिक केस चलाने के निर्देश दिये थे। डीडीए अधिकारियों की भूमिका को जांचने को भी कहा था।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट ● फाइल फोटो

36 अधिकारियों की इस मामले में मिलीभगत की पुष्टि हुई

24 जनवरी को दोबारा निर्माण के दिए थे एलजी ने आदेश

इनकी भूमिका संदिग्ध

- तीन सदस्य (इंजीनियरिंग)
- छह मुख्य अभियंता
- नौ अधीक्षक अभियंता
- नौ कार्यकारी अभियंता
- चार सहायक अभियंता
- आठ कनिष्ठ अभियंता

विजिलेंस जांच में ये तथ्य सामने आए

- अपार्टमेंट के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा
- निर्माण में इस्तेमाल सामग्री बेहद घटिया थी
- इमारत को जांच में असुरक्षित बताया गया

सैकड़ों जान खतरे में

उपराज्यपाल के आदेश पर डीडीए ने विजिलेंस जांच कराई।
जांच से डीडीए अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से कमजोर इमारत खड़ी करने की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं डीडीए को करोड़ों रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा है। डीडीए ने सीबीआई को पत्र लिखकर तत्कालीन डीडीए अधिकारियों, निर्माण करने वाली कंपनी, इमारत की जांच करने वाली कंपनी आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

निजी स्कूल बगैर अनुमति फीस नहीं बढ़ा सकेंगे

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों से फीस बढ़ोतरी के संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं, जिसको लेकर निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने आदेश जारी किया है। निदेशालय की अनुमति के बिना स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डीडीए/अन्य भू- स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा आवंटित जमीन पर संचालित स्कूलों से फीस वृद्धि को

- शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर चेतावनी दी

लेकर यदि कोई प्रस्ताव है, उसे देने के निर्देश हैं। निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से 27 मार्च तक विभाग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अधूरा प्रस्ताव बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया जाएगा।

किसी भी स्कूल द्वारा प्रस्ताव को मैन्युअल रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
SUNDAY
MARCH 05, 2023

Hindustan Times

DDA FILES PLAINT AGAINST OFFICIALS OVER 'UNSAFE' N DELHI FLATS

HT correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has filed a complaint with the Central Bureau of Investigation (CBI) to lodge FIR against erring DDA officials and contractors allegedly behind poor construction quality of Signature View apartment in Mukherjee Nagar.

The move came after directions from lieutenant governor VK Saxena, officials in the LG office said on Saturday. The apartment was built during 2007–2009 and was allotted to residents in 2011-2012, but in just a few years, the building became structurally unsafe. LG is DDA's chairman.

Taking note of "grave lapses", the LG on January 24, 2023 ordered "immediate initiation of criminal proceedings against the contractors/builders/construction agencies" and an inquiry to identify DDA officials responsible for lapses in the construction of the buildings and subsequent criminal action against the defaulting officials, according to a statement by the LG's office.

APERS-- THE SUNDAY EXPRESS, MARCH 5, 2023

DDA lodges complaint with CBI over 'lapses' in flat construction

New Delhi: The DDA has lodged a complaint with the CBI against erring DDA officials, contractors/builders responsible for poor construction quality of Signature View Apartments. Officials said this follows the directions of L-G Saxena. The apartments were built during 2007 and 2009 and allotted to residents between 2011 and 2012; in just a few years, however, the building had become structurally unsafe.

DDA asks CBI to file FIR against 39 of its officers

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Development Authority has asked the CBI to register an FIR against 39 of its officers apart from various contractors who were involved in "faulty construction" of multistorey Signature View Apartments in north Delhi's Mukherjee Nagar in 2009 and putting hundreds of lives at risk.

The officials are three DDA members (engineering), six chief engineers, nine superintending engineers, nine executive engineers, four assistant engineers and eight junior engineers.

▶Points at collusion, P 2

LG allows teachers' trip, govt slams riders

LG V K Saxena Saturday gave nod to allow teachers to train in Finland but with certain conditions, which the **AAP government called a "fraud upon (sic) the Constitution and the SC". P 2**

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MARCH 5, 2023

'Inquiry points at collusion between officials & builders'

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: Taking serious note of "grave lapses" in construction of the multistorey Signature View Apartments in north Delhi's Mukherjee Nagar, LG V K Saxena had asked DDA on January 24 to initiate criminal proceedings against the erring contractors, builders and construction agencies while conducting a vigilance inquiry to identify all DDA officials responsible for lapses and misconduct and begin criminal proceedings against them.

Built during 2007-09, the 336 flats — 112 MIG and 224 HIG, were allotted in 2011-12 but the buildings became structurally unsafe within a few years. "The action is a stern message from the LG to all government officers against any collusion, misconduct, laxity. There is zero tolerance for corruption and any compromise with the interest and safety of the people of Delhi will not be tolerated," a Raj Nivas official said.

According to officials, the construction agencies against whom DDA has requested CBI to register FIR included Winner Construction Pvt Ltd and Grover Construction Pvt Ltd apart from two testing agencies — Bharat Test House and Delhi Test House — for offences of "cheating, criminal breach of trust, endangering life and public safety of others and other relevant provisions of the Prevention of Corruption Act".

A senior Raj Nivas official said a vigilance inquiry established "collusion" between the DDA officials and builders and contractors resulting in "compromising the quality and structural safety requirement during the construction, thereby causing wrongful loss to DDA besides putting to peril the lives and property of hundreds of residents".

The vigilance inquiry also found out that the provisions pertaining to quality control as mentioned in the contract and the CPWD manual were bypassed, owing to which the construction failed in less than a decade, said an official.

"The concrete in the structure at most locations was found to be of a lower grade. Despite several repairs, the structural stability continued to fail to an extent that an independent expert suggested immediate evacuation," an official quoting the vigilance department report said.

"It was the duty of the contractor and officers concerned to ensure that prescribed norms of quality control and terms and conditions of the agreement were followed. It appears that either the officers failed to point out deficiencies during construction or effectively colluded with the agency to compromise the quality and provide wrongful gains to the agency," the official added.

A study by an IIT-Delhi expert found the building to be structurally unsafe and recommended that it may be vacated and dismantled at the earliest.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
SUNDAY
MARCH 05, 2023

SPAPERS----------DATED----------

Delhi HC stays NGT order on tree pruning in Vasant Vihar

Richa Banka
richa.banka@htlive.com

NEW DELHI: The Delhi high court has put on hold pruning of trees in south Delhi's Vasant Vihar area after a petition was filed against an order of the National Green Tribunal (NGT) that permitted clipping of tree branches.

Sanjeev Bagai, a Padma Shri awardee, had moved the high court challenging the NGT's January 19 order, contending that around 800 trees in the area have been pruned or chopped off, without following proper procedure and guidelines.

In an order of March 1, justice Najmi Waziri said that a more detailed assessment by the RWA needs to be carried out, adding that "further pruning in the area concerned has to be stopped right-away".

The court appointed advocate Aditya N Prasad as amicus curiae to assess the situation at the site and assist the court, while also issuing notices to the authorities seeking to know their stand on the petition.

It further directed the Tree Officer, Deputy Director (Horticulture) South Zone, Station House Officer, Vasant Vihar police station, Deputy Director (Horticulture)-PWD, Executive Engineer, PWD, Deputy Director (Horticulture)-MCD, Deputy Director (Horticulture)-DDA along with the petitioners and/or their representatives to be present at the Municipal Corporation of Delhi (MCD) office in Vasant Vihar on March 5 to assist the amicus curiae.

ACCORDING TO THE HC, THE RESIDENTS' BODY APPROACHED NGT FOR PERMISSION FOR PRUNING. THE BODY, HOWEVER, SAID IT DID NOT MOVE COURT

The court listed the matter for hearing on March 10.

According to the high court order, the green tribunal's January 19 order came on a representation by the Vasant Vihar RWA, known as Vasant Vihar Welfare Association. According to the court order, the residents' body said it wanted to prune certain trees in the colony and had approached the civic body and the Tree Officer but nothing worthwhile came forth. Following this, it sought the NGT's intervention.

The association, however, said it did not petition the NGT.

Appearing for the petitioner, senior counsel Vivek Sibal contended that the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, provides statutory protection to trees in Delhi, and the essential part of preservation is that a tree should not be damaged in a manner which would impede its growth or otherwise severely affect its regrowth and regeneration.

Referring to the photographs attached to the petition, he submitted that quite a few trees have been chopped off in the guise of pruning, causing extensive damage to trees and setting back the greenery in certain areas of the colony by a decade or a decade and a half.

"The pruning would have to be only with strict permission of the Tree Officer and not on general guidelines. Once a 'woody plant' gets classified as a tree, any alteration to its body or being will have to be in terms of the procedure prescribed under section 9 of the Act. That procedure has not been followed in the present case; therefore, the entire process, adopted towards pruning of trees, is illegal," the counsel had said.

The RWA, however, clarified that it did not petition the NGT seeking permission for pruning of trees.

"We did not petition NGT as has been erroneously recorded in the high court order. The MCD had carried out the pruning activities in accordance with the NGT order, and the RWA assisted it as directed by NGT. The NGT's order was very clear that MCD, being the civic body, should carry out the pruning activity. Pruning is an essential work that has to be done to maintain the trees' good health. As a matter of fact, the guidelines specify that pruning up to 15.7 cm does not require any permission from the forest department. The Tree Officer had given a detailed report to the NGT on pruning in the area and now that the high court has sought that report. We will wait for it," said Gurpreet Singh Bindra, president of Vasant Vihar Welfare Association.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

------DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, MARCH 6, 2023

G20 Guests On Nature Trail Along Yamuna

Saxena Hosts Diplomats From 11 Countries

TIMES NEWS NETWORK

Anindya Chattopadhyay

The visitors went for a walk & bird watching in the riverine ecosystem

New Delhi: Diplomats from 11 countries visited Asita East, a biodiversity park on the Yamuna floodplain, to participate in a nature trail and a bird-watching tour, Raj Niwas officials said on Sunday.

The exercise was planned to showcase Delhi's natural heritage before the world leaders congregating in the capital for various G20 events.

Lieutenant governor V K Saxena hosted the envoys at Asita East, which is being restored by the Delhi Development Authority. "Ambassadors and other diplomats of 11 countries visited Asita East early morning and went on a nature trail and bird-watching tour along the floodplain, spotting over 30 species of birds," said a senior official from LG's house.

The place has varied flora and fauna, including rare migratory birds, he said.

"The diplomats also went cycling through the vast grasslands of Asita East. Considering the eco-sensitive character of the area, the visitors left their vehicles right at the entrance on Vikas Marg and took electric carts to reach the floodplain. Some of the visitors also preferred walking down to the floodplain," he said.

The foreign diplomats appreciated the rich bio-diversity and the efforts undertaken to restore the ecological character of the Yamuna, the statement from the LG's house added.

LG SAYS

Just six months ago, this fragile riverine eco-system was a dumpyard of waste, squatters and stray animals

G20 Sherpa Amitabh Kant was also present on the occasion.

Saxena lauded the efforts that have gone into rejuvenating the Yamuna floodplain and exhorted all stakeholders to put in collective effort in undoing the destruction caused to the natural heritage due to rampant urbanisation. "Asita has been our own effort at such rejuvenation. Just six months ago, this fragile riverine ecosystem was a dumpyard of waste, squatters and stray animals. Persistent efforts by DDA have resulted in salvaging a self-contained ecosystem that houses rich natural diversity," Saxena said.

Though the Yamuna floodplain remained fragile, efforts were being made to restore and rejuvenate Delhi's natural heritage that was crucial for making the capital environmentally sustainable with a refurbished green blue ecosystem, he said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 6 मार्च, ----------DATED----------

सेंट्रल पार्क के फ्लावर फेस्टिवल में दिखेगी जी-20 देशों की झलक, होगी प्रतियोगिता

फेस्टिवल 11 और 12 मार्च को होगा आयोजित, एनडीएमसी ने शुरू की तैयारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जी-20 के मद्देनजर फूड और ट्यूलिप फेस्टिवल के आयोजन के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अब फ्लावर फेस्टिवल की तैयारी शुरू कर दी है। 11और 12 मार्च को कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार व नगर निगम समेत अन्य विभागों और संस्थाओं के साथ जी-20 देशों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल पार्क में इसकी तैयारी के लिए एनडीएमसी ने अलग तरीके का फूलों का पिरामिड तैयार किया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य जी-20 के सदस्य और अतिथि देशों की जीवंतता और रंगीन प्रदर्शन को भारत की राजधानी में प्रदर्शित करना है।

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली का प्रमुख पर्यटक वाणिज्यिक आकर्षण का केंद्र है। हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक और नागरिक आते हैं। यह फ्लावर फेस्टिवल जी-20 सदस्यों और अतिथि देशों के बारे में आम जनता के बीच प्रचार और जागरूकता का अवसर है। इसमें विभिन्न रंगों व किस्मों के फूलों के पौधों को विभिन्न रूपों, स्थापनाओं और संरचनाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

कनाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क मे फूलों की सजावट से बनाया गया पिरामिड ● हरीश कुमार

एनडीएमसी भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न फूलों के पौधों को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने बताया कि इस फेस्टिवल के लिए जी-20 के अतिथि देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें एनडीएमसी उनको निश्शुल्क तौर पर स्थान उपलब्ध कराएगा। अतिथि देश फूलों और गमलों में लगे अन्य पौधों की विभिन्न किस्मों को या तो स्थानीय रूप से या उनके देश में उत्पादित हों, वे उन्हें यहां प्रदर्शित कर सकते हैं।

इन विभागों की रहेगी मौजूदगी: इस फ्लावर फेस्टिवल में एनडीएमसी के साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, नोएडा और गाजियाबाद प्राधिकरण को आमंत्रित किया गया है। इसमें कई की सहमति भी मिल गई है। इसके अतिरिक्त लुटियंस दिल्ली में मौजूद विभिन्न राज्यों के भवनों और सदनों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

चित्रकला प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन: वनस्पतियों और जीवों की थीम पर स्कूली बच्चों के बीच स्थल पर चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। फेस्टिवल में डहलिया, बोगेनविलिया, पत्तेदार पौधे, बोन्साई, कैक्टस और पाटेड पौधों में रसीले पौधे, हैंगिंग बास्केट, फ्लोरल फिगर, ट्रे गार्डन व फ्लोरल अरेंजमेंट्स आदि जैसे रंगीन और जीवंत फूलों के विभिन्न वर्गों को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया जाएगा।

सुबह 10 से शाम सात बजे तक का होगा आयोजन: एनडीएमसी के सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक इस उत्सव का आयोजन होगा। इसमें नागरिकों का प्रवेश निश्शुल्क होगा। प्रवेश कनाट प्लेस के डी ब्लाक के सामने वाले गेट से होगा। लोग विभिन्न स्टाल से अपने पसंदीदा पौधे व फूल आदि भी खरीद सकते हैं। इस अवसर पर प्रदर्शनी देखने आए आगुतंकों के लिए एनडीएमसी सेंट्रल पार्क एम्फीथिएटर में साइट पर मनोरंजन के लिए संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, MARCH 6, 2023 ----------DATED----------

L-G hosts diplomats from G20 countries at biodiversity park

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 5

Ambassadors and diplomats of 11 countries visited the park and went on a nature trail and bird watching tour

IN A bid to showcase Delhi's natural heritage to world leaders who are in the national capital for various G-20 events, Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena Sunday hosted envoys/diplomats at Asita East, a biodiversity park on the Yamuna floodplains.

According to L-G House officials, the event was also attended by Minister of State for External Affairs Meenakshi Lekhi. Ambassadors and diplomats of 11 countries visited the park early in the morning and went on a nature trail and bird watching tour, spotting over 30 species of birds.

Officials said Saxena lauded the efforts that have gone into rejuvenating the floodplains and exhorted all stakeholders to put in collective efforts in undoing the destruction caused to natural heritage due to rampant urbanisation.

"Asita has been our own effort at such rejuvenation. Just six months ago, this fragile riverine eco-system was a dump yard of waste, squatters and stray animals. Persistent efforts by the Delhi Development Authority has resulted in salvaging a self-contained ecosystem that houses rich natural diversity. Though the Yamuna floodplains remain fragile, efforts are on to restore and rejuvenate Delhi's natural heritage that is crucial for making the city environmentally sustainable with a refurbished green-blue ecosystem," said Saxena.

Asita East is spread over 90 hectares of land. It was rejuvenated by restoring the natural depressions, creating catchment zones, reviving the floodplain forests and grasslands and creating favourable habitats especially for water and terrestrial birds.

"This floodplain, due to years of neglect, had degraded into a dumping ground and was largely encroached upon by squatters However, with the intervention of the Delhi High Court, squatters were removed and the entire area was reclaimed by the DDA," said officials.

Further, Asita East has a restored wetland of about 2.5 hectares that is augmenting more than 60 million litres of water.

It has a plantation of 4,000 native trees of floodplain ecosystem and about 3.35 million riverine grasses planted in a record time of six months. This attracted about 63 varieties of resident and migratory birds this winter, said officials.

An interactive public zone has also been created with large congregation spaces, nature trails, cycle tracks and a selfie point, said officials.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 6 मार्च 2023 ----------DATED----------

असिता ईस्ट की खूबसूरती पर फिदा हुए G20 समिट में आए प्रतिनिधि

11 देशों के प्रतिनिधियों ने रविवार को यमुना नदी के किनारे पक्षियों के बीच गुजारा अपना वक्त

NBT@G20

■ **विस, नईदिल्ली :** जी-20 के तहत 11 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को असिता ईस्ट की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। यमुना किनारे बने इस खूबसूरत इको फ्रेंडली पार्क में उनके लिए नेचर ट्रेल और पक्षियों को निहारने की गतिविधियों का आयोजन भी हुआ। एलजी वीके सक्सेना ने इन प्रतिनिधियों की मेजबानी की।

डीडीए ने असिता ईस्ट को 6 महीने में तैयार किया है

डीडीए ने इस जगह को 6 महीने में तैयार किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। 11 देशों के प्रतिनिधी और राजदूत रविवार सुबह असिता ईस्ट पर पहुंचे। यहां पर उन्हें 30 प्रजातियों के पक्षी भी दिखाई दिए। विदेशी प्रतिनिधियों ने साइकल से असिता ईस्ट की सैर की। यहां के इको सेंसेटिव नेचर को देखते हुए विदेशी प्रतिनिधियों ने अपनी गाड़ियों को बाहर पार्किंग में ही छोड़ दिया। इसके बाद वह अंदर इलेक्ट्रिक कार्ट से पहुंचे। कुछ प्रतिनिधियों ने पैदल ही पार्क तक पहुंचना पसंद किया।

वीके सक्सेना ने कहा कि पहले यहां पर काफी कूड़ा था।

एलजी ने विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी की

इसे पार्क में बदलना चुनौतीपुर्ण भी रहा। यमुना का बाढ़ क्षेत्र राजधानी में 90 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें से अभी असिता ईस्ट का काम पूरा किया गया है। इसके तहत यहां केचमेंट जोन, बाढ़क्षेत्र में जंगल, घास की जमीन बनाकर पक्षियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। असिता ईस्ट झील 2.5 हेक्टेयर में फैली है और इसमें 60 मीलियन लीटर से अधिक पानी है। इसमें चार हजार से अधिक पेड़ हैं और 3.35 मीलियन घास लगाई गई है। यहां पर 63 प्रजातियों के पक्षी रह रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
MONDAY
N MARCH 06, 2023 Hindustan Times --------DATED----------------------

LG hosts G20 diplomats at Asita biodiversity park

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Sunday hosted diplomats from some of the G20 countries participating in the summit later this year at the newly developed Asita East biodiversity park built along the floodplains of the Yamuna.

An official from the LG secretariat said ambassadors and diplomats of 11 countries visited Asita East early on Sunday.

"The envoys went on a nature trail and birdwatching tour along the floodplains, spotting over 30 species of birds. The site hosts diverse vegetation and features rare migratory birds. These diplomats also went cycling through the vast grasslands of Asita East," the official said on condition of anonymity, adding that Union minister of state for external affairs Meenakshi Lekhi was also present for the outing.

LG Saxena with G20 diplomats at the Asita biodiversity park. ANI

Considering the ecologically sensitive character of the area, the visitors left their vehicles at the entrance of the floodplains on Vikas Marg and took electric carts to reach the biodiversity park, the official said.

Spread over 90 hectares, Asita East has been developed by the Delhi Development Authority (DDA) as part of its ambitious Yamuna riverfront redevelopment project. Work on the project started in 2017 and it was inaugurated by the LG in September last year.

"Just six months back, this fragile riverine ecosystem was a dump yard of waste, squatters and stray animals. Persistent efforts by DDA have resulted in salvaging a self-contained ecosystem. Though the Yamuna floodplains remain fragile, efforts are being made to restore and rejuvenate Delhi's natural heritage that is crucial for making Delhi environmentally sustainable," Saxena said.

Asita East has a restored wetland of about 2.5 hectares. "It has a plantation of 4,000 native trees of the floodplain ecosystem and 3.35 million riverine grasses, which has attracted 63 varieties of resident and migratory birds this winter to make it their home," he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times | NEW DELHI MONDAY MARCH 06, 2023

Delhiwale

EXPERIENCE YOUR CITY LIKE NEVER BEFORE

Mayank Austen Soofi

Jumping jack for dummies

Exercising along a park trail

PRIVATE CAPITAL

It's not rocket science. Try deciphering the directives painted on the board:

- Stand erect
- Feet together
- Jump stride
- Bringing arms to shoulder level

Follow these, and the Delhi Development Authority (DDA) — its seal is painted on a similar board nearby — might just help you become a "Jumping Jack".

Tucked by the fashionable Hauz Khas Village, Deer Park, like most public gardens in the city, is managed by the DDA. The garden's Swasth Path (health trail) is lined with a series of metal signages, each painted with the name of an exercise, accompanied with bulleted how-to-do instructions. See yourself some of the exercise names: Lateral Exercise, Balancing Beam, Straddle Walk, and the aforementioned Jumping Jack.

Certainly, you, dear reader, will be able to obey the instructions flawlessly, but some of us might find these as challenging as the lines of any convoluted Emily Dickinson poem. Take this random sample— "Lie down on bench, keep feet under strip, sit up, keep hand locked behind neck".

A few steps ahead on the trail, a board pops up amid the picturesque wilds, saying:
Straddle Walk and Jump

- Walk stepping
- Either side of log
- Jump hurdlers jump of with both feet

Here's another board:

- Swing left arm forwards
- Backwards
- Keep right elbow pressed back.
- Repeat same with other arm

While here, you may as well read this board too:

- Stand erect
- Legs apart
- Circle arms forward and backward
- Repeat alternatively

An expat living in the vicinity once told this reporter that "the instructions for the exercises bring back memories of being at yoga ashrams in Kerala and Uttarakhand. We Westerners often have blind faith in the words of the yoga gurus as we contort our bodies into twisted knots. I would be happy to 'push the poll repeat with right foot alternatively' in my attempts to find my inner nirvana."

And here is a must-see board advising the fitness fanatic to take a break.

"You May Relax Here:
Leave Your Body
Loose And Breath:
Be In A Easy Condition
And Tune With Nature"

Nearby, two lovers are sitting, holding hands, in tune with each other, and with the nature.

READ: For more stories by Mayank Austen Soofi, scan the QR code